EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
Useful For Prelims
Date: 18-Nov-2025

जानें-समझें

परमाणु परीक्षण के लिए ट्रंप का आदेश

रणनीतिक संतुलन के सवाल पर चिंता बढ़ी

जनसत्ता संवाद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश देकर वैश्विक रणनीतिक संतुलन को झकझोर दिया है। इस घोषणा से एक ओर अमेरिका द्वारा नई परमाणु नीति की तैयारी का संकेत मिला है। दूसरी ओर, चीन, रूस और भारत जैसे देशों के सामने भी मुश्किल रणनीतिक विकल्प खड़े हो गए हैं।

तीस साल बाद कवायद

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। दरअसल, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही कुछ समय के लिए इस बारे में विचार किया गया था। अमेरिका का तर्क है कि परमाणु भंडार की विश्वसनीयता और प्रदर्शन को बनाए रखने की आवश्यकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का तर्क, 'यह सुनिश्चित करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है कि हमारे पास जो परमाणु भंडार है, वह वास्तव में सही ढंग से काम करे और यह परीक्षण की व्यवस्था का एक हिस्सा है।' अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है।

चिंता कितनी वाजिब

परमाणु हथियार की विश्वसनीयता को लेकर ट्रंप प्रशासन की चिंताएं दूर की कौड़ी लगती हैं, क्योंकि प्रयोगशालाओं (कंप्यूटर-सिम्युलेटेड टेस्टिंग, हाइड्रो-न्यूक्लियर टेस्टिंग और प्रयोगशाला के वातावरण में सब-क्रिटिकल टेस्टिंग) में इसकी उन्नत क्षमता का प्रदर्शन हो चुका है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन दुनिया पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में है। साथ ही, वह अपने नए विकसित कुछ आयुधों का परीक्षण करना चाहता है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन (एनएनएसए) ने मई 2025 तक पहला 'बी61-13 ग्रैविटी बम' विकसित कर लिया। यह नए विकसित बमों में से पहला है। अमेरिका के पास बी61-12 बम हैं, जिनकी सटीकता और विनाशकारी ताकत जबरदस्त है। नया बी61-13 कठोर लक्ष्यों को ज्यादा भेदता है और बड़े इलाके में इसका असर होता है। यह एनएनएसए के द्वारा चलाए जा रहे 'युद्धाग्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के तहत सात नए आयुधों में से एक है।

परमाणु भंडार का आधुनिकीकरण

अमेरिका में बी61-12 ग्रैविटी बम का आखिरी उत्पादन दिसंबर 2024 में किया गया। यह वो समय था जब दूसरा ट्रंप प्रशासन सत्ता में आ रहा था। इससे साफ है कि अमेरिका के परमाणु भंडार के आधुनिकीकरण को लेकर सभी दलों की सहमति है। दूसरी ओर, चीन सब-क्रिटिकल परीक्षण के माध्यम से कम-से-कम अपने मौजूदा परमाणु आयुधों का परीक्षण करने में काफी सक्रिय रहा है और नए डिजाइन के परीक्षण के लिए अपने लोप नूर परमाणु स्थल को तैयार कर रहा है। भारत में विश्लेषकों का मानना है कि परमाणु परीक्षण पर 30 साल की अमेरिकी रोक को हटाने वाले ट्रंप के नए एलान के बाद चीन और रूस परमाणु परीक्षण करेंगे। दूसरी ओर, लोप नूर में चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण की तैयारी के सबूत का इस्तेमाल अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण को उचित ठहराने के लिए करेगा।

भारत की दुविधा

भारत के सामने कठिन विकल्प हैं। वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई थी। तब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। फिर क्लिंटन प्रशासन के दौर में स्ट्रोब टैलबाट और जसवंत सिंह के बीच परमाणु वार्ता हुई, जो जार्ज डब्लू बुश प्रशासन में भी चलती रही और नतीजा 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के रूप में आया। फिर भारत और अमेरिका में 123 समझौते को लेकर बातचीत हुई और 2008 में परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) ने स्पष्ट रूप से छूट दी, जिससे परमाणु ईंधन, तकनीक और वाणिज्य तक भारत की पहुंच आसान हो गई।

(फाइल फोटो)

परमाणु परीक्षण ऐसा मसला है, जिसमें भारत को ट्रंप प्रशासन के मनमानेपन से जूझना होगा। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता नाजुक दौर में है, भारत को परीक्षण की संभावना को रोकने की गारंटी देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

- एअर मार्शल (सेवानिवृत्त) अनिल खोसला

मौजूदा कूटनीतिक स्थिति का मतलब यह नहीं है कि भारत को कभी भी परीक्षण रोकने के अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए। बल्कि पूरी तरह रणनीतिक कारणों से इस तरह के बड़े फैसले को टालना बुद्धिमानी होगी, भले ही अमेरिका या चीन कुछ भी करें।

- मोहन कुमार, पूर्व राजनयिक

खतरनाक बी61-12 बम

अमेरिका अपने नए विकसित कुछ आयुधों का परीक्षण करना चाहता है। वहां के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन (एनएनएसए) ने मई 2025 तक पहला 'बी61-13 ग्रैविटी बम' विकसित कर लिया। उसके पास बी61-12 बम हैं, जिनकी सटीकता और विनाशकारी ताकत जबरदस्त है। नया बी61-13 कठोर लक्ष्यों को ज्यादा भेदता है और बड़े इलाके में इसका असर होता है। यह 'युद्धाग्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के तहत सात नए आयुधों में से एक है।

गुंजाइश कम

वर्ष 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौता सामने आया। फिर 123 समझौते को लेकर बातचीत हुई और 2008 में परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) ने छूट दी। इस 123 समझौते के तहत भारत के पास अतिरिक्त परीक्षण के लिए बेहद कम गुंजाइश है। भारत नए परमाणु परीक्षण करेगा तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

Jansatta Page No-7

Hindustan Page No-1

व्यक्तित्व

दिवी बिजेश : महज नौ साल की उम्र, शतरंज में मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

जनसत्ता संवाद

दिवी बिजेश तिरुवनंतपुरम की सिर्फ नौ साल की शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो चौंसठ खानों की ज्यामिति में दस चालें आगे देख सकती हैं – जानती हैं कि कब मुसीबत से बाहर निकलना है, कब घोड़ा किनारे पर होना चाहिए, कब मोहरा जीतने के लिए बढ़ेगा। वे शतरंज की बिसात को एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह पढ़ती हैं। जनवरी में उन्हें अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) द्वारा 'वुमन कैंडिडेट मास्टर' का खिताब दिया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं दिवी।

उनके पिता बिजेश एस कहते हैं, 'मेरे बेटे देवनाथ बिजेश ने सबसे पहले शतरंज खेलना शुरू किया था। दिवी उसकी साथी बनकर खेलने लगी। उस समय वह सिर्फ सात साल की थी। जब हम अपने बेटे के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गए, तो हमने सोचा कि उसे भी इसमें हिस्सा लेने दिया जाए। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था, उसने राष्ट्रीय अंडर-7 गर्ल्स चैंपियनशिप में खेलना शुरू कर दिया। वह उपविजेता रही। वह बड़ा मोड़ था। हमने उसे पेशेवर कोचिंग देने का फैसला किया।'

तब से दिवी ने शतरंज की बिसात और मोहरों के साथ अपना सफर शुरू किया और अब तक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 60 से ज्यादा खिताब जीते हैं। हाल ही में, दिवी ने ग्रीस के रोड्स में आयोजित फिडे वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में पूरे देश का नाम रोशन किया।

अंडर-10 बालिका वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने रैपिड प्रारूप में अपनी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए 11 में से 10 अंक हासिल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तिरुवनंतपुरम के एलन फेल्डमैन पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा, दिवी अपने शतरंज करिअर और स्कूली जीवन के बीच संतुलन बनाते हुए कक्षा में भी कामयाब रहती हैं।

टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला चयनात्मक टूर्नामेंट, जिसमें कोई वित्तीय पुरस्कार नहीं मिलता, केवल प्रमाणपत्र और देश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिलता है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) द्वारा आयोजित किया जाता है और सभी खिलाड़ियों के लिए खुला होता है। ये किसी की प्रतिभा का आकलन करते हैं।

बिजेश बताते हैं, 'हमने ज्यादातर चयन स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। अब हम अपना ध्यान उच्च-स्तरीय स्पर्धाओं पर केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। हमारा अगला बड़ा लक्ष्य जार्जिया में होने वाले आगामी विश्व कप में भाग लेना है।'

दिवी का कहना है, 'जब मैं खेलती हूं तो मुझे घबराहट नहीं होती। मैं बस इसका आनंद लेती हूं।'

सम-सामयिक

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में कसौटी पर रक्षा संबंध

जनसत्ता संवाद

भारत और अमेरिका के रिश्तों का सबसे मजबूत स्तंभ है रक्षा साझेदारी। दो दशकों में हुई हथियारों की खरीद, तकनीकी हस्तांतरण और हिंद- प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तालमेल से यह बात साबित होती है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुल्क को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच व्यापार वार्ता को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों में रक्षा संबंध कसौटी पर हैं। खतरा यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्तों का स्वरूप कहीं क्रेता-विक्रेता के स्वरूप में ढलने न लग जाए।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे आपसी संबंधों में दूरी बढ़ी है। हालांकि आपसी रिश्तों में आशा जगाने वाली प्रगति जारी रखी गई है। फिर भी ट्रंप के रवैए के कारण सोच बनी है कि दोनों देशों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ के बीच वार्ता हुई थी। उसके बाद राजनियक चैनल के माध्यम से बातचीत चल रही है। जिस रक्षा समझौते का मसविदे पर दोनों देश सहमत हुए, उसे भारत-अमेरिका सहयोग का अहम मोड़ बताया गया।

तालमेल का सवाल

भारत और अमेरिका, दोनों ही देशों को नए दशकीय समझौते को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोनों यह भी सुनिश्चित करें कि यह साझेदारी साझा नजरिए, आपसी भरोसे और रणनीतिक गहराई से ताकत पाती रहे। आगे की योजनाओं पर काम करना होगा। वर्ष 2035 में करार का नवीकरण होना चाहिए। वहां तक की यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों ही पक्ष इस रास्ते पर चलते हुए कितना सहयोग, सामंजस्य और समन्वय बनाए रख पाते हैं। सुरक्षा और रक्षा संबंधों का नया अध्याय भी इसी से तय होगा।

भारत-अमेरिका रिश्तों का सबसे मजबूत आधार है रक्षा साझेदारी। दो दशकों में रक्षा, तकनीक और हिंद-प्रशांत तालमेल गहरा हुआ है। नए रक्षा समझौते को चार कारणों से अहम माना जा रहा है। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा शुल्क लाद रखे हैं। दूसरी बात यह है कि भारत-अमेरिका रिश्तों में रक्षा और व्यापार का चोली-दामन जैसा साथ रहा है। इस दीर्घकालिक रक्षा समझौते से उम्मीद बनी है कि व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत देर-सबेर पटरी पर आ ही जाएगी। समझौते से न केवल भारत को अहम रक्षा उपकरणों की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, बल्कि तकनीकी सहयोग और उसके हस्तांतरण की भी राह आसान बनी है।

भारत और अमेरिका में रक्षा भागीदारी 1995 में शुरू हुई। इसे 2005 में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने बढ़ाया, जब भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के नए ढांचे पर हस्ताक्षर किए गए। जून 2015 में मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐश कार्टर ने नए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत-अमेरिका में रक्षा और सुरक्षा रिश्तों के लिहाज से 2025 के करार से नया रोडमैप तैयार होगा। युद्ध का स्वरूप जी से बदल रहा है। इस समझौते को खास तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता, प्रतिरोध, तकनीकी सहयोग और सूचनाओं के लेन-देन के लिहाज से खास माना जा रहा है। यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर दीर्घकालिक सामरिक नजरिया अपनाता है। इसमें मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद – प्रशांत पर जोर दिया गया है, इससे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर घटते भरोसे को इससे थोड़ी मजबूती मिलती है।

दूसरी ओर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की घोषित प्रतिबद्धता और चीन के साथ आर्थिक समझौते पर पहुंचने की उसकी बेकरारी में विरोधाभास दिखता है। आसियान शिखर बैठक के दौरान हाल में हुए अमेरिका-चीन आर्थिक समझौते ने अमेरिकी कंपनियों को राहत भले पहुंचाई हो, इसने क्वाड ढांचे के तहत भारत, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा बनाए गए तालमेल के लिए चिंता बढ़ाई है।

Jansatta Page No-7

व्यापार घाटे की खाई हुई चौड़ी

अक्टूबर में निर्यात 11.8 फीसदी घटा, अमेरिका को निर्यात में 8.6 फीसदी की गिरावट

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 17 नवंबर

भारत का माल व्यापार घाटा अक्टूबर में बढ़कर 41.68 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सोने का आयात तीन गुना बढ़ने और निर्यात में 14 महीनों में सबसे तेज गिरावट आने की वजह से व्यापार घाटा बढ़ा है। पिछले साल अक्टूबर में व्यापार घाटा 26.22 अरब डॉलर था और सितंबर 2025 में यह 32.15 अरब डॉलर था जो 13 महीने का उच्च स्तर था।

अक्टूबर में आयात 16.64 फीसदी बढ़ा और यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 76.06 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सोने का आयात पिछले साल की तुलना में 199.2 फीसदी बढ़कर 14.72 अरब डॉलर हो गया जो दबी हुई मांग और त्योहारी सीजन की वजह से है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के एक भागीदार देश से चांदी के आयात में वृद्धि के कारण अक्टूबर में चांदी का आयात छह गुना बढ़कर 2.72 अरब डॉलर हो गया।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया, 'साल के पहले छह महीनों में मात्रा के लिहाज से सोने का आयात 25 फीसदी घटा था, जिसका असर त्योहारी मांग के कारण अक्टूबर में दिखा, जिससे आयात में वृद्धि देखने को मिली और व्यापार घाटा बढ़ गया।'

अक्टूबर में देश से वस्तुओं का निर्यात 11.8 फीसदी घटकर 34.38 अरब डॉलर रहा। इस गिरावट का कारण उच्च आधार माना जा सकता है। अमेरिका, सिंगापुर और नीदरलैंड सहित भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को भी निर्यात में कमी देखी गई। ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 8.6 फीसदी की कमी आई।

वाणिज्य सचिव ने कहा, 'निर्यात घटने के पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला, ऊंचा आधार क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में 38.98 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। अमेरिका को निर्यात के मामले में हम अपनी स्थिति टिकाऊ बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।'

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सोने का आयात तीन गुना बढ़ा

- अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर
- त्योहारी मांग के कारण सोने का आयात तीन गुना बढ़कर 15.72 अरब डॉलर रहा
- कुल आयात 16.64 फीसदी बढ़कर 76.06 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
- अक्टूबर में निर्यात 34.38 अरब डॉलर रहा, अमेरिका सहित अन्य बाजारों में घटा निर्यात

व्यापार करार का पहला चरण जल्द

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण 'पूरा होने के करीब' है और यह कई भारतीय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क की समस्या को दूर करेगा। उन्होंने कहा, 'हम द्विपक्षीय व्यापार करार पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके दो भाग हैं। एक भाग की बातचीत में समय लगेगा। दूसरा भाग एक पैकेज है जो जवाबी शुल्क की समस्या को दूर कर सकता है। हम दोनों पहलुओं पर काम कर रहे हैं। समझौते का वह भाग जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह पारस्परिक शुल्क है, जिस पर जल्द ही ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। दोनों देश संपर्क में हैं।'

Business Standard Page No-3

जुलाई में 5.2 तथा मई और जून में 5.6 फीसद थी | सर्वेक्षण | ग्रामीण बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट आई है

बेरोजगारी दर अक्तूबर में 5.2 फीसद पर स्थिर

: नई दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा)।

देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों में अक्तूबर में बेरोजगारी दर 5.2 फीसद पर स्थिर रही। सोमवार को जारी एक सरकारी सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआइ) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, बेरोजगारी दर (यूआर) सितंबर में 5.2 फीसद, अगस्त में 5.1 फीसद, जुलाई में 5.2 फीसद तथा मई और जून में 5.6 फीसद थी। मई, 2025 में जारी प्रथम पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार, अप्रैल में बेरोजगारी दर 5.1 फीसद थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सितंबर, 2025 और अक्तूबर, 2025 के बीच 5.2 फीसद पर अपरिवर्तित रही।' बयान के अनुसार, ग्रामीण बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट आई है। यह सितंबर, 2025 के 4.6 फीसद से अक्तूबर, 2025 में 4.4 फीसद रह गई है। शहरी बेरोजगारी दर 6.8 फीसद से बढ़कर 7.0 फीसद हो गई है। बयान में कहा गया कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में बेरोजगारी दर सितंबर, 2025 के 5.5 फीसद से घटकर अक्तूबर, 2025 में 5.4 फीसद रह गई। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में सितंबर, 2025 के 4.3 फीसद से अक्तूबर, 2025 में 4.0 फीसद तक की गिरावट की वजह से समग्र महिला बेरोजगारी दर में गिरावट आई। पुरुषों में बेरोजगारी की दर पिछले महीने की तुलना में अक्तूबर, 2025 में 5.1 फीसद पर स्थिर रही। ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी सितंबर, 2025 में 4.7 फीसद से अक्तूबर, 2025 में 4.6 फीसद तक थोड़ी कम हुई, जबकि शहरी पुरुषों में बेरोजगारी में 6.0 फीसद से 6.1 फीसद तक मामूली वृद्धि हुई, जिससे कुल बेरोजगारी स्थिर रही। अक्तूबर, 2025 में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्लूपीआर) 52.5 फीसदथा, जो जून, 2025 से लगातार बढ़ रहा है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआइ) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, बेरोजगारी दर (यूआर) सितंबर में 5.2 फीसद, अगस्त में 5.1 फीसद, जुलाई में 5.2 फीसद तथा मई और जून में 5.6 फीसद थी। मई, 2025 में जारी प्रथम पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार, अप्रैल में बेरोजगारी दर 5.1 फीसद थी।

Jansatta Page No-10

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया

रूस से खरीदा तेल तो लगेगा 500 फीसद शुल्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 नवंबर।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा, उस पर 'बहुत कड़ी पाबंदियां' लगाई जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन और रिपब्लिकन सांसद मास्को को निशाना बनाने वाले कड़े कानून पर आगे बढ़ रहे हैं।

रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप से पूछा गया कि क्या रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस द्वारा उपाय लागू करने का समय आ गया है, इस पर उन्होंने कहा, 'मैंने सुना है कि वे ऐसा कर रहे हैं और यह ठीक है।' ट्रंप ने कहा, 'वे कानून पारित कर रहे हैं, रिपब्लिकन कानून ला रहे हैं , रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वे उसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं, यह सुझाव मैंने दिया था।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया, 'तो कोई भी देश जो रूस के साथ व्यापार करेगा, उसे बहुत कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। हम इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं।' ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसद शुल्क लगाया है जो दुनिया में सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। इसमें रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 फीसद का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। सांसद लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए एक विधेयक में रूसी तेल की द्वितीयक खरीद और पुनः बिक्री पर 500 फीसद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को संसद की विदेश संबंध समिति में लगभग सर्वसम्मत समर्थन मिला है। ग्राहम और सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने संयुक्त रूप से 'रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025' पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन देशों पर द्वितीयक शुल्क और प्रतिबंध लगाना है जो यूक्रेन में पुतिन के बर्बर युद्ध को जारी रखने के लिए धन मुहैया कराते हैं।' इस प्रस्तावित कानून के संसद में 85 सह-प्रायोजक हैं।

एक रपट के अनुसार, जुलाई में जारी एक संयुक्त बयान में, सीनेटरों ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने एक शक्तिशाली कदम उठाया है, रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया दृष्टिकोण लागू किया है। हालांकि, इस युद्ध को खत्म करने के लिए अंतिम हथौड़ा चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ शुल्क होगा, जो सस्ते रूसी तेल और गैस खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन का समर्थन करते हैं।' ट्रंप ने कहा, 'जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा, उसे बहुत कड़े प्रतिबंध झेलने होंगे। इसमें ईरान को शामिल करने का सुझाव भी मैंने ही दिया था।' अमेरिका किसी भी देश को रहत नहीं देगा, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना ही बड़ा क्यों न हो।

रूस को अलग-थलग करने की रणनीति

ट्रंप प्रशासन पहले ही दुनिया के कुछ सबसे कड़े शुल्क लगा चुका है, जिसमें भारत पर 50 फीसद शुल्क और रूसी ऊर्जा की खरीद पर 25 फीसद शुल्क शामिल है। अमेरिकी सीनेटर इससे भी कड़े प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए एक बिल में रूसी तेल की द्वितीयक खरीद और पुनर्विक्रय पर 500 फीसद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, जिसे सीनेट की विदेश संबंध समिति में समर्थन प्राप्त है।

Jansatta Page No-11

भारतीय वायु सेना और फ्रांस की वायु एवं अंतरिक्ष सेना (एफएएसएफ) के अधिकारियों ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'गरुड़-25' में हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना ने सोमवार को तस्वीर जारी कर कहा कि वायु सेना के सुखोई-30एमकेआई और फ्रांस के राफेल विमान आसमान में छा गए।

Business Standard Page No-7

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान दिया

दस साल में मैकाले की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का आग्रह किया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न केवल उभरता हुआ बाजार है, बल्कि आत्मविश्वास से भरे एक नए माडल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने रामनाथ गोयनका की पत्रकारिता के मिशन को याद किया, जो लोगों के विरोध की आवाज को मुखरित करता रहा है।

नई दिल्ली, 17 नवंबर (जनसत्ता)।

चाहे ब्रिटिश राज हो या आपातकाल, एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका ने गुलामी के प्रयासों के खिलाफ जन प्रतिरोध को मूर्त रूप दिया और असहमति की ताकत को स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि यही वह भावना है, जो 1835 से भारत में पैठ जमा चुकी उस पश्चिमी मानसिकता पर 'ताले लगाने' के राष्ट्रीय संकल्प का मार्गदर्शन करेगी, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को ध्वस्त कर और औपनिवेशिक शिक्षा को लागू करने की थामस मैकाले की परियोजना के माध्यम से स्थापित हुई थी।

छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान देते हुए प्रधानमंत्री ने दस साल की समयसमीमा के भीतर उस विरासत से मुक्ति के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक नींव को खोखला करने के लिए मैकाले द्वारा किए गए अपराध को 2035 में 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

मोदी ने कहा कि मैकाले का उद्देश्य ऐसे भारतीयों को तैयार करना था जो 'दिखने में तो भारतीय हों, लेकिन दिल से अंग्रेज हों।' उन्होंने कहा कि भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस धारणा ने जड़ें गहरी जमा ली कि पश्चिमी या विदेशी श्रेष्ठ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैकाले ने भारत का आत्मविश्वास तोड़ा और हीनता का भाव पैदा किया। एक ही झटके में उसने भारत के हजारों वर्षों के ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और पूरी जीवन-शैली को नकार दिया।

मोदी ने कहा कि यह छाप आजादी के बाद भी बनी रही, क्योंकि भारत की शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक **बाकी पेज ८ पर**

नई दिल्ली में सोमवार को छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। *ताशी तोबग्याल*

THE RAMNATH GOENKA LECTURE 2025
Presented by
360 ONE
Co-presented by
SANJAY KAKADE GROUP
ELIXER
WORLD TRADE CENTER
JK LAKSHMI
Tulip
abp न्यूज़

Jansatta Page No-1

बांग्लादेश के आइसीटी ने मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए सुनाया फैसला

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 नवंबर।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए सोमवार को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई।

महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आइसीटी) ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का 'मुख्य सरगना और प्रमुख सूत्रधार' **बाकी पेज ८ पर**

हसीना ने कहा, फैसला एक गैरअधिकृत न्यायाधिकरण का।
बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए भारत प्रतिबद्ध : विदेश मंत्रालय

बांग्लादेश ने भारत से हसीना को सौंपने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 17 नवंबर (ब्यूरो)।

भारत में प्रवास कर रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना को तुरंत सौंपने का आग्रह किया है।

-पूरी खबर पेज ८

Jansatta Page No-1

नीतीश ने की विधानसभा भंग करने की सिफारिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 नवंबर।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और 19 नवंबर से मौजूदा राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। उसी दिन, कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और अगली सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी सहयोगियों का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होगा।

बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी **बाकी पेज ८ पर**

नीतीश 19 को दे सकते हैं इस्तीफा, 20 को लेंगे शपथ। *चौधरी* ने बताया कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर कैबिनेट के निर्णय से उन्हें अवगत कराया।

राजद विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव

नई दिल्ली, 17 नवंबर (**ब्यूरो**)।

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की समीक्षा बैठक में राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लालू प्रसाद यादव ने कहा, तेजस्वी ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की।

-पूरी खबर पेज ८

Jansatta Page No-1

तेजस्वी होंगे नेता प्रतिपक्ष

पटना (एसएनबी)। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद में हार के कारणों पर चर्चा के लिए चार घंटे तक मैराथन बैठक चली। चुनाव परिणाम के तीसरे दिन तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी के सरकारी आवास पर

- राजद की हार पर चार घंटे तक हुआ मंथन
- चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी, महागठबंधन की बैठक में होगा फैसला

राजद की बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव को गुलदस्ता भेंट कर शुभकामना देते नवनिर्वाचित विधायक।

विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में जीते और हारे दोनों उम्मीदवारों के अलावा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, सूरजभान सिंह समेत राजद के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक करीब चार घंटे तक चली। बैठक में चुनाव में हार की समीक्षा भी की गई।

राजद नेताओं के मुताबिक बैठक में सभी से बात की गयी। चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट जाने पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की भी राय ली जाएगी। राजद नेता के मुताबिक चुनाव में गड़बड़ी हुई है। तेजस्वी आवास पहुंचे विधायक ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस तरह का परिणाम आया है। चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, एनडीए की जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने जीविका दीदियों का वोट खरीदा है। चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वोटिंग से पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजे गए। कहा जा रहा था, सरकार बना दीजिए तो 2 लाख और देंगे। चुनाव में चोरी और धांधली की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने चुनाव में हारने वाले सभी प्रत्याशियों को विशेष रूप से बुलाया है। वह प्रत्येक उम्मीदवार से फीडबैक लेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर क्या गलत हुआ। बैठक में चुनावी हार के पीछे स्थानीय असंतोष, संगठनात्मक राजनीति, बूथ मैनेजमेंट की कमी और चुनावी मुद्दों को सही तरीके से जनता तक न पहुंचा पाने जैसी संभावित वजहों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

Rashtriya Sahara Page No-2

बालश्रम एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या

मो. कामिल खां

भारत में बाल श्रम की स्थिति काफी गंभीर है, जहां लाखों बच्चे विभिन्न उद्योगों में काम करने को मजबूर है बच्चों का एक महत्वपूर्ण यर अनुपात बाल श्रम में लगा हुआ है विशेष कर कृषि, निर्माण एवं घरेलू कार्यों में मजदूरी करते है आंकड़ों की दृष्टि से भारत में 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या मे लगभग 6 करोड़ बच्चे है भारत में 10 मिलियन से अधिक बच्चे हानिकारक परिस्थितियों में मजदूरी करने को मजबूर है जो कुल बच्चों की कुल आबादी 3.9 फीसदी है ।जो विभिन्न प्रकार के बाल श्रम में लगे है भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चे लगभग 9 मिलियन के आसपास है।

भारत में बच्चों की आबादी मे से काफी अधिक संख्या में बच्चे मजबूरी और पेट पालने हेतु काम एवं कच्ची उम्र से ही मजदूरी में लग जाते है एक बार मजदूरी में फंसे बच्चे इसके? बाद बाहर नही निकाल पाते बच्चों के लिए कोई बालश्रम का कार्य की दृष्टि से हानिकारक ही माना जाता है, क्योंकि अपने देश में बालश्रम की स्थिति दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। वास्तव में देश में बढ़ती आबादी,गरीबी, सामाजिक असमानता बाल श्रम के मुख्य कारण है। देश में लगभग दो करोड़ बच्चे बाल श्रम में सक्रियता से लगे है। इनमें 55 फीसदी उत्तर प्रदेश ,बिहार राजस्थान, महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है । हाल के कुछ वर्षों में बालश्रम में कमी आई है ।विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में बाल श्रमिक जहां बढ़े है वही ग्रामीण क्षेत्रो में इनकी संख्या घटी है है । ऐसे मे इस महत्वपूर्ण समस्या को निराकरण के लिए प्रयास की जरूरत है।

विडंबना यह है कि विभिन्न प्रयासों से जितने बच्चों को श्रम बाजार से मुक्त कराया जाता है उससे अधिक बच्चे श्रमिक के रूप मे बाजार में पहुंच जाते है जिससे उनकी संख्या मे कमी आने के बजाय वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1971 की जनगणना के मुताबिक बाल श्रमिकों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख थे, जो वर्ष 1981 में बढ़कर एक करोड़ 11 लाख हो गई जबकि 1986 में एक करोड़ 73 लाख बताई गई। 1991 में जनगणना के अनुसार भारत में एक करोड़ 42 लाख 18588 बाल श्रमिक थे 1999 से 2000 में एक करोड़ चार लाख हो गई 2001 में एक करोड़ 25 लाख बाल श्रमिक लगे थे राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ताजा अनुमानों के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 22 करोड़ के करीब है जो कुल आबादी का 20 फीसदी है। एक स्वयं सेवी संगठन के अनुसार 2.5 करोड़ बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर और दो करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्ण कालिक श्रमिक के रूप मे तथा एक करोड़ 50 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्य करते है 2005 में बाल श्रमिकों की संख्या का अनुमान 5 से 6 करोड़ रहा जिसमें वृद्धि हो रही है।

वास्तव में बालश्रम अपने आप में निरीह एवं निरपवाद शब्द है ,किंतु जब यह दोनों मिलकर बालश्रम बन जाते है तो एक विकट सामाजिक बुराई का रूप ले लेते है । एक विद्वान के अनुसार, बालश्रम किसी बालक द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिसे सीधे तौर पर स्वयं बालक को या फिर उसके परिवारजनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से किया जाए जिससे उसके स्वयं के शारीरिक ,मानसिक या सामाजिक विकास मे बाधा पहुंचे ऐसे बच्चे समाज के लिए देश के लिए चिंताजनक स्थिति है।

बाल श्रमिक मुख्य रूप से दो क्षेत्र में पाए जाते है असंगठित क्षेत्र में- होटल, ढाबा, फैक्ट्री व दुकान ऑटो वर्कशॉप अखबार बेचना, कोयला, कचरा चुनना ,खेती -बाड़ी ,घर में नौकर का काम करना आदि है । संगठित क्षेत्र में- कालीन उद्योग ,दियासलाई आतिशबाजी ,हथकरघा चमड़ा ,कांच ,भवन निर्माण पत्थर खदान ,रत्न उद्योग और ताला उद्योग आदि है।

बालश्रम के कारणों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो अत्यधिक निर्धनता, रोजगार के अवसरों कमी कमी अनिश्चित आजीविका और निम्न स्तरीय जीवन- शैली बालश्रम को बड़े पैमाने पर फैलाने के मुख्य कारण। वैसे शिक्षा का अभाव बाल श्रमिकों के विकास में काफी सहायक है। पहले खेती के कामों में लगे रहते थे किंतुऔद्योगिकरण और शहरीकरण के बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय में बाल श्रमिकों को बड़े पैमाने पर नियोजित किया जाने लगा। बाल -बालिका श्रमिक का यौन शोषण मालिकों ठेकेदारों ,एजेंट ,सहकर्मियों, अपराधियों आदि द्वारा किया जाता है ताकि बच्चों में इतना डर पैदा कर दिया जाए कि वह शोषण के विरुद्ध आवाज ना उठा सके ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बाल श्रमिकों कान केवल उनके श्रम का इस्तेमाल होता है बल्कि उनका भरपूर शोषण भी किया जाता है। बाल मजदूरों का शारीरिक शोषण भी इधर बहुत अधिक होने लगा है।सर पर बोझ ढोने ,ज्वलनशील भट्ठियों में काम करने ,कोई चीज खींचने के लिए अंतिम दम तक जोर लगाने, गंदे बदबूदार कार्यों को के कारण उनकी अनुमानित आय एक तिहाई रह जाती है ।खान एवं खदानों में बच्चों को भेजने की प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि कि उनमें वयस्क नहीं घुस सकते इसके लिए उनकी मजबूरी होती है कि वह बच्चे सुरंग में जाकर के कम करें । जब वह बड़े होते तो उनकी छटनी कर दी जाती है। शोर करने वाले मशीनों पर प्राय बच्चे बहरे हो जाते है और धूल के कारण उन्हें तरह-तरह की बीमारी हो जाती है।

बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नही है इसमें बाल श्रम की अधिनियम 1986 शामिल है। इसके उपबंधों के अनुसार 13 जोखिम भरी व्यवसायों और 57 जोखिमकारी प्रक्रिया में बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है ।बाल मजदूरों में नियोजकों को संलिप्तता पर उन्हें दंडित किया जाने का प्रावधान भी है। बाल मजदूरी से बच्चों को मुक्त कराने हेतु छापों की पद्धति प्रयोग में लाई जाती है और बच्चों को मुक्त कराया जाता है ,लेकिन जिम्मेदारी की सीमा यही समाप्त नही हो जाती जिससे बच्चों को मुक्त कराया जाय और उसके बाद ही वह समाप्त हो जाती है बल्कि असली जिम्मेदारी की शुरुआत यही से होती है अर्थात मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से समन्वय से विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों का सीधा लाभ बाल मजदूरों को और उनके परिवारों को दिया जाए जिससे उन परिवारों को बाल मजदूरों के जरिए मिलने वाली आय की वैकल्पिक व्यवस्था हो सके और वह इसका लाभ उठा सकें इतना ही नही ऐसे गरीब एवं वंचित परिवारों में स्वास्थ्य पोषाहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते खाद्यान्न कपड़े एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिससे उन परिवारों में मृत्यु दर और जन्म दर कम हो तथा उनकी औसत आई बढ़े।

बाल श्रमिकों को मुक्त करने के पश्चात उनके पुनर्वास की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है अन्यथा बाल श्रमिक आजीविका के साधनों से वंचित रह जाए कर और सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख होकर अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते है पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ाना बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा दी जाए स्कूली पाठ्यक्रमों में बाल श्रम प्रथा उन्मूलन का अध्याय शामिल किया जाए बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि वह स्कूलों की तरफ जाएं और अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें जिससे बाल मजदूरी पर नियंत्रण किया जा सकता है वैसे यह भी सच है की बाल श्रम उन्मूलन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नही है वास्तव में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए बाल श्रम को एक सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हुए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए इसके लिए जागरूकता की जागरूकता की नितांत आवश्यकता है जिसमें समाज योगदान होना चाहिए । वास्तव में बालश्रम जैसी सामाजिक एवं आर्थिक समस्या के लिए जरूरी है कि बचपन सीखने के लिए है श्रम के लिए नही है ,उनके हाथों में किताबे हो, कारखाने में वह न जाने पाए ऐसी स्थिति में बाल श्रम जैसी देश की प्रमुख समस्या पर सरकार के साथ सभी की जिम्मेदारी बनती है ताकि कि इस पर नियंत्रण किया जा सके।

पेश होगा कंपनी विधेयक!

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 17 नवंबर

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता, अपराध को कम करना और स्पष्टीकरण लाना है। इस विधेयक में विभिन्न पेशेवरों को फर्म का हिस्सा बनने की अनुमति देकर देसी बहुविषयक प्रैक्टिस फर्म की स्थापना से संबंधित प्रावधानों को भी आसान बनाने की उम्मीद है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी की अध्यक्षता में बिग फोर के भारतीय संस्करण तैयार करने पर समिति छोटी लेखा और लेखा परीक्षा फर्मों के विस्तार में मदद करने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है। सरकार ने अवधारणा नोट में कहा था कि फर्मों पर अन्य पेशेवरों के साथ साझेदारी पर रोक ने उन्हें नुकसान में डाल दिया है।

भारत के नियमों में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस), वकील और मुनीम जैसे पेशेवरों को एक ही फर्म संरचना के तहत एक साथ काम करने की अनुमति नहीं है। इससे सहयोग और अंतरराष्ट्रीय फर्मों द्वारा दी जाने वाली एकीकृत सेवाएं प्रदान करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को अपने कुछ कार्यों को अपने कार्यकारी बोर्ड के बाहर सौंपने के वास्ते और अधिक अधिकार देने पर भी विचार कर रहा है ताकि इसके जांच और अनुशासनात्मक कार्यों को बांटा जा सके।

इस साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि कार्यों के विभाजन की कमी एनएफआरए पर पक्षपात के आरोपों, पहले से तय राय को चुनौती देने की प्रवृत्ति और समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से तर्कों की अवहेलना के आरोपों को उजागर करता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि नियम तकनीकी नवाचारों और वैश्विक नीति विकास के साथ बने रहें।

उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों और विश्वास पर आधारित एक हल्के-फुल्के नियामक ढांचे का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा था, 'इस ढांचे के जरिये हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए नियमों को अद्यतन करेंगे।' कंपनी कानून समीक्षा समिति ने दो साल पहले कंपनी अधिनियम में बदलावों के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद, विधेयक में और बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए कैबिनेट नोट में भी शामिल किया गया है।

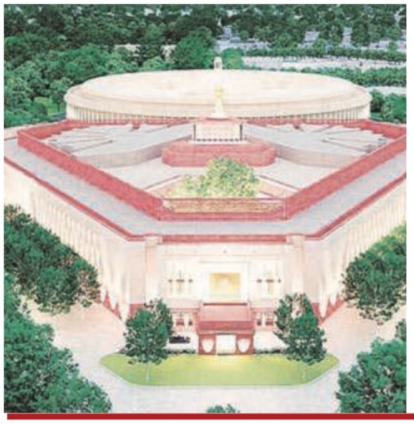

शीत सत्र में पेश होगा

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट नोट को दिया मूर्त रूप
- संशोधन विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता, अपराध को कम करना और स्पष्टीकरण लाना है
- अभी सीए, सीएस, वकील व मुनीम जैसे पेशेवरों को एक ही फर्म संरचना के तहत एक साथ काम करने की अनुमति नहीं है
- कंपनी कानून समीक्षा समिति ने दो साल पहले कंपनी अधिनियम में बदलावों के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दिया

व्यापार मेले में आकर्षण का केंद्र बना डायनासोर का अंडा और उल्कापिंड

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 17 नवंबर।

भारत मंडपम में आयोजित 44वेंअंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उल्कापिंड, लिथियम और साढ़े छह करोड़ साल पुराना शाकाहारी डायनासोर का अंडा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय खनिज मंत्रालय के मंडप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्टाल पर प्रदर्शित इन बहुमूल्य खनिज संपदा को लोग उत्सुकतापूर्व देखने के लिए आ रहे हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक डाक्टर प्रवीर पंकज ने बताया कि हम जीवन में रोजमर्रा की वस्तुओं में प्रयोग होने वाले खनिज से लेकर अत्याधुनिक सामानों में प्रयोग होने वाले खनिज को लेकर आए हैं जोकि मोबाइल बैटरी, सोलर पैनल, वाहनों सहित विभिन्न सामानों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं। खास बात यह है कि यहां आसमान, धरती व समुद्र से मिलने वाले खनिजों को प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान, कश्मीर व कर्नाटक से मिलने वाला लिथियम देखा जा सकता है। तांबा, जस्ता, बाक्साइट, ग्रेफाइट व

डायनासोर का अंडा और उल्कापिंड।

पौधों सहित कई प्रकार के जीवाश्म भी देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार हमने सोरोपाड डायनासोर के अंडे (जीवाश्म) को यहां रखा है। ये डायनासोर शाकाहारी होता है। इसके अंडे की दोहरी परत और उसके पास से मिले शौच की गहन शोध के बाद पता चला की ये शाकाहारी डायनासोर है और उसका जीवाश्म जोकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मिला था वो साढ़े छह करोड़ साल पुराना है।

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने सोमवार को भारत मंडपम में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली पुलिस के मंडप का उद्घाटन किया।

अमेरिका में नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 17 फीसद की गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 नवंबर।

अमेरिका के कालेजों और विश्वविद्यालयों में नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में 2025 के शरद सत्र में 17 फीसद की कमी आई है। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में लगातार दूसरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामले में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 'ओपन डोर्स' रपट अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों तथा अकादमिक क्रेडिट के लिए विदेश में अध्ययन कर रहे अमेरिकी छात्रों के बारे में सबसे व्यापक सूचना स्रोत है।

Jansatta Page No-1

अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात का करार

शुभांगी माथुर
नई दिल्ली, 17 नवंबर

सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम उपक्रमों ने अमेरिका से 22 लाख टन सालाना तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के आयात के लिए एक वर्षीय अनुबंध को पहली बार अंतिम रूप दिया।

यह एलपीजी आयात सौदा ऐसे समय में हुआ है जब भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत जोर पकड़ रही है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और भारत निष्पक्ष व्यापार समझौते पर पहुंचने के 'बहुत करीब' थे।

केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनुबंध की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की खाड़ी के तट से अनुबंध वर्ष 2026 के लिए एलपीजी आयात होना है और यह भारत के सालाना एलपीजी आयात का करीब 10 प्रतिशत है। यह भारतीय बाजार के लिए पहला ऐसा अमेरिकी एलपीजी अनुबंध है।

दरअसल, भारत अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष को कम करने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र के दोनों देशों के व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने में केंद्रीय भूमिका निभाने की संभावना है।

पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, 'यह खरीद एलपीजी खरीद के लिए माउंट बेलव्यू

अमेरिका की खाड़ी के तट से अनुबंध वर्ष 2026 के लिए एलपीजी आयात होना है। यह भारतीय बाजार के लिए पहला ऐसा अमेरिकी एलपीजी अनुबंध है

हरदीप सिंह पुरी,
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करने पर आधारित है। हमारे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अधिकारियों के दल ने अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने बीते कुछ महीनों में अमेरिका के प्रमुख उत्पादकों से बातचीत की थी।'

भारत अपनी एलपीजी की घरेलू जरूरतों के लिए करीब 60 प्रतिशत आयात पर निर्भर रहता है। भारत की एलपीजी की 90 प्रतिशत जरूरतें पश्चिम एशिया के देशों जैसे यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब से पूरी होती हैं। इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत एलपीजी के आयात के स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है।

पुरी ने इस करार के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह एक वर्षीय समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है और यह लाखों घरों को सस्ता व खाना बनाने का स्वच्छ ईंधन भी उपलब्ध कराएगा।

भारत की तेल कंपनियां अमेरिका से एलपीजी के अलावा भी कच्चे तेल के आयात को बढ़ावा दे रही हैं। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म कैप्लर के मुताबिक भारत का अमेरिका से कच्चे तेल का आयात मार्च 2021 के बाद अक्टूबर में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। भारत के कच्चे तेल की आयात बॉस्केट में अमेरिका की बढ़ती हिस्सेदारी यह इंगित करती है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों की जड़ें गहरी हो रही हैं। यह भी प्रदर्शित होता है कि भारत की रणनीति आपूर्ति की सुरक्षा, अर्थशास्त्र और भूराजनीति को संतुलित करना है। भारत कच्चे तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और एलपीजी का बड़ा आयातक है। भारत के इन तीन ईंधनों का आयात अमेरिका से बढ़ने की उम्मीद है।

Business Standard Page No-4

Useful For Mains

रोग प्रतिरोधक दवाओं का मकड़जाल

रोग प्रतिरोधक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से भारत में खतरनाक स्थिति पैदा होती जा रही है, जहां दवाएं बेअसर हो जाती हैं और सामान्य बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। चिंता की बात यह है कि मुर्गी पालन और पशुपालन में भी इन दवाओं का अत्यधिक उपयोग हो रहा है।

प्रदीप श्रीवास्तव

किसी भी बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक दवाएं (एंटीबायोटिक) बहुत कारगर मानी जाती हैं, यही वजह है कि बाजार में ये दवाएं सबसे ज्यादा बिकती हैं। हालांकि, इनके अंधाधुंध इस्तेमाल से देश में 'सुपरबग्स' जैसी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जहां दवाएं बेअसर हो जाती हैं और सामान्य बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। चिंता की बात यह है कि मुर्गी पालन और पशुपालन में भी रोग प्रतिरोधी दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। नतीजतन, अगर हम खुद रोग प्रतिरोधी दवाएं कम लें, तो भी यह समस्या दूसरे रूप में हमें घेरे रहेगी। इसलिए सरकार की ओर से इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

वर्ष 1928 में लंदन के एक चिकित्सा संस्थान में कार्यरत स्काटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं पर शोध करते हुए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। दूसरे विश्वयुद्ध में जब लाखों घायल सैनिक संक्रमण से मर रहे थे, तब पेनिसिलिन एक वरदान साबित हुई। इससे अनगिनत सैनिकों की जान बचाई गई। पेनिसिलिन ने चिकित्सा विज्ञान की दिशा बदल दी और इसे आधुनिक एंटीबायोटिक युग की शुरुआत माना जाता है। हालांकि, 1945 के बाद से फ्लेमिंग खुद चेतावनी देते रहे कि रोग प्रतिरोधक दवाओं के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से प्रतिरोध पैदा होगा और यही हुआ।

अब यह समस्या और बड़ी बनने लगी है, क्योंकि भारत जैसे देशों में बिना चिकित्सक की सलाह के रोग प्रतिरोधी दवाएं लेना, अधूरा दवा लेना और छोटी-मोटी बीमारी में भी इनका इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। इन दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे शरीर में जीवाणु या विषाणु दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं और यह स्थिति 'सुपरबग्स' के रूप में उभरकर सामने आती है। यानी ऐसी स्थिति जिसमें ताकतवर जीवाणु या विषाणु दवाओं से नहीं मरते और उन पर साधारण रोग प्रतिरोधक दवाएं काम नहीं करती। ऐसे में न सिर्फ मरीजों पर दवाओं का खर्च बढ़ता जाता है, बल्कि भविष्य में यह स्थिति कई अन्य बीमारियों को न्योता देती है और सामान्य संक्रमण यानी खांसी, बुखार या घाव होने पर भी इलाज मुश्किल हो जाता है।

पहले जिन बीमारियों का इलाज सामान्य एवं सस्ती दवा से हो जाता था, उनके लिए अब महंगी दवाएं या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि सामान्य बीमारी पर भी दवाएं बेअसर होती हैं तथा इलाज के लिए कई तरह की जांच करानी पड़ती है और नए किस्म की दवाएं देनी पड़ती हैं। बार-बार रोग प्रतिरोधक दवाएं लेने से एलर्जी और त्वचा पर दाने जैसी समस्याएं भी आने लगती हैं और लंबे समय में गुर्दा, लीवर और पेट पर असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दवाएं हानिकारक जीवाणुओं के साथ-साथ अच्छे जीवाणुओं को भी मार देती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रपट के अनुसार, देश में हर साल लगभग सात लाख लोग एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि अगर इस समस्या पर रोक नहीं लगी, तो वर्ष 2050 तक भारत समेत विश्व में इस स्थिति से करीब एक करोड़ लोगों की मौत प्रति वर्ष हो सकती है।

भारत में रोग प्रतिरोधक दवाओं का बाजार बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां

संक्रमण संबंधी बीमारियां आम हैं। वर्ष 2023 में देश में यह बाजार करीब 49,000 करोड़ रुपए का था। अनुमान है कि वर्ष 2024-2030 के बीच यह बाजार लगभग 6-7 फीसद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मालूम हो कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रोग प्रतिरोधक दवाओं का उत्पादक देश है। 'द लांसेट' की 2022 की एक रपट के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति रोग प्रतिरोधक दवाओं की खपत दुनिया में सबसे अधिक है। अनुमान है कि हर साल देश में लगभग 1,300 करोड़ से अधिक की खुराक इन दवाओं की ली जाती है। सरकार ने 'शेड्यूल एच1' लागू किया है, जिसके तहत कई रोग प्रतिरोध दवाएं केवल चिकित्सक के परामर्श पर ही मिल सकती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 'एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप' कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, ताकि इन दवाओं का दुरुपयोग कम हो, लेकिन समस्या जस की तस है।

> **भारत में रोग प्रतिरोधक दवाओं का बाजार बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां संक्रमण संबंधी बीमारियां आम हैं। वर्ष 2023 में देश में यह बाजार करीब 49,000 करोड़ रुपए का था। अनुमान है कि वर्ष 2024-2030 के बीच यह बाजार लगभग 6-7 फीसद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मालूम हो कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रोग प्रतिरोधक दवाओं का उत्पादक देश है। सन 2022 की एक रपट के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति रोग प्रतिरोधक दवाओं की खपत दुनिया में सबसे अधिक है। अनुमान है कि हर साल देश में लगभग 1,300 करोड़ से अधिक की खुराक इन दवाओं की ली जाती है।**

भारत में सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार और अतिसार जैसी बीमारियों से हर साल करीब 30-35 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। वर्ष 2024 तक देश में कुल पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या लगभग 13 लाख हैं, इनमें से 10.4 लाख एलोपैथिक और 4.5 लाख आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार, एक हजार की आबादी पर कम से कम एक चिकित्सक होना चाहिए। जबकि भारत में एक हजार की आबादी पर मात्र 0.7 चिकित्सक उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात और भी कम है, कई राज्यों में तो एक हजार की आबादी पर मात्र 0.2 चिकित्सक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2023 की रपट की मानें तो देश में 1.55 लाख उप-स्वास्थ्य केंद्र, 25,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5,600 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से लगभग 65-70 फीसद स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। भले ही देश में करीब एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण इलाकों में हों, लेकिन अभी भी यहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी है।

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोग प्रतिरोधक दवाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला, वे दवाएं जो सामान्य संक्रमण के लिए सुरक्षित हैं और इनका शरीर पर कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी श्रेणी में उन दवाओं को रखा गया है, जिनका इस्तेमाल सीमित तौर पर ही किया जाना चाहिए और इनके लिए निगरानी जरूरी है। तीसरी श्रेणी में वे दवाएं हैं, जिन्हें केवल जीवन-रक्षक स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मगर इन दिशा-निर्देशों पर पूरी तरह अमल नहीं हो पा रहा है। यह समस्या इसलिए भी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि इंसानों के साथ ही कृषि और पशुपालन क्षेत्र में भी रोग प्रतिरोधक दवाओं का अंधाधुंध उपयोग होने लगा है, खासतौर से मुर्गीपालन और पशुपालन में।

खाद्य और कृषि संगठन (संयुक्त राष्ट्र), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट के अनुसार, भारत में रोग प्रतिरोधक दवाओं की कुल खपत का पचास फीसद से अधिक हिस्सा पशुपालन में इस्तेमाल होता है। दूध देने वाले मवेशियों में संक्रमण रोकने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इन दवाओं का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 2022 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10-12 फीसद दूध के नमूनों में इन दवाओं के अवशेष मौजूद थे। अनुमान है कि देश में हर साल लगभग 70-75 फीसद मुर्गी पालकों द्वारा चारे में रोग प्रतिरोधक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। सरकार के नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य रोग प्रतिरोधक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और भविष्य में गंभीर संक्रमण के इलाज के लिए उनकी प्रभावशीलता बनाए रखना है। यदि मरीज, चिकित्सक, अस्पताल और किसान सभी मिलकर इन नियमों का पालन करें, तो इस समस्या पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

Jansatta Page No-6

मोदी व सुशासन बाबू की मेहनत लायी रंग

बिहार चुनाव

शिव शंकर गोस्वामी

बिहार विधानसभा के बहु प्रतीक्षित चुनाव का परिणाम आ गया है। दो तिहाई वोट एनडीए के खाते में गया है। इसमें कई अन्य बातें उभर कर सामने आई है । मसलन सुशासन बाबू को अब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का शुभ अवसर मिलेगा। दूसरी बात यह की जंगल राज बनाम सुशासन के बीच में बिहार की प्रबुद्ध जनता ने सुशासन का साथ दिया और जंगल राज तथा परिवारवाद को सिरे से खारिज कर दिया। तीसरी बात यह है कि इस चुनाव में सुशासन बाबू द्वारा महिलाओं को रु. 10000 नगद देने का फार्मूला काम आया और महिलाओं ने जमकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसके अलावा एक बात और सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ,भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री एवं बड़े नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। उसी का नतीजा रहा कि एनडीए को बिहार में तीन चौथाई से अधिक मत मिला है। बिहार में इसे अगर एनडीए की सुनामी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि अपने बढ बोलेपन और बचकानी हरकत के लिए तेजस्वी बाबू ने जो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की घोषणा की थी वह उनकी इच्छा धरी की धरी रह गई और एक बात यह भी कि इस चुनाव में बिहार की जनता ने तालाब में कूदने वाले और मोटरसाइकिल पर करतब करने वाले तथा चुनाव के दौरान अमेरिका और ब्राजील की यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सिरे से खारिज कर दिया और अब यह भी तय है कि कल से ही यह हारे हुए नेता लोग वोट चोरी की माला जपने लगेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी लहर काम करती हैं लेकिन बिहार में सत्ता विरोधी लहर ने बिल्कुल कम नहीं किया बल्कि सत्ताधारी पार्टी ने और उनकी सरकार ने जो काम किया उसी को आधार मानकर लोगों ने बंपर वोट दिया और यह साबित कर दिया की वह विकास और सुशासन के साथ है उन्हें जंगल राज और झूठे वादे कतई पसंद नही है। महिलाओं ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि जो उनके लिए काम करेगा वह उसके साथ खड़ी होंगी इसीलिए चुनाव के दौरान महिलाओं ने जमकर वोटिंग की और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 70 फीसदी से ऊपर लोगों ने मतदान किया इसमें महिलाओं का प्रतिशत 60 से ऊपर बताया जाता है। इस चुनाव में बिहार के महा जननायक कर्पूरी ठाकुर फैक्टर ने भी काम किया। जातव्य है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने अभी पिछले साल ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से

सम्मानित किया था। इससे अति पिछड़ों और पिछड़ों का वोट भाजपा और एनडीए के पक्ष में गया। आमतौर पर चुनाव में धांधली को लेकर के तरह-तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते रहे है और भविष्य में भी लगाए जाएंगे लेकिन एक बात साफ हो गई है कि बिहार के चुनाव में ना तो कहीं पुनर मतदान हुआ और ना भी कही हिंसा हुई जबकि इसके पहले दर्जनों जगहों पर पुनर मतदान हुआ करता था और दर्जनों लोग मारे जाते थे।

बिहार की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सेवा भाव खूब रास आया। देश के यह दोनों ऐसे नेता है जिन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल की हवा खाकर आ चुके है और आज भी उन पर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में मुकदमा चल रहा है। इस बात को जनता ने अच्छी तरह से समझ लिया कि अगर लालू और उनका कुनबा फिर से पावर में आया तो बिहार में केवल लूटपाट और जंगल राज होगा जबकि नीतीश कुमार को 8-10 बार से लोग देख रहे है की ना तो उन्होंने कोई परिवार वाद के सिद्धांत पर काम किया और ना ही उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो भ्रष्टाचार के आरोप का कोई सवाल ही पैदा नही होता। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दहाई तक की सीट नहीं मिली। जो सीटें मिली है वह लोगों के व्यक्तिगत काम से मिली है उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व या राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है क्योंकि चुनाव के दौरान मोटरसाइकिल पर बैठकर करतब दिखाने वाले अथवा तालाब में कूदकर मछली पकड़ने वाले या पदयात्रा करने की नौटंकी करते रहे या फिर वह विदेश में जाकर अय्याशी करते रहे।

इस चुनाव में पहली बार जन स्वराज पार्टी के बैनर तले प्रशांत किशोर ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीद उतारे थे। और लगभग हर सीट पर लड़ रहे थे लेकिन टांय टांय फिस्स हो गये। लेकिन उन्हें इतनी भी सीट नहीं मिली कि उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सदन में बैठ सके। इस बार के चुनाव से दो बातें और सामने आई है । नंबर एक यह कि जो बिहार जातिवाद के लिए विख्यात रहा है वहां जातिवाद का असर बिल्कुल नहीं दिखा और जनता ने सुशासन एवं विकास के नाम पर वोट दिया ।

दूसरी बात यह है कि चुनाव परिणाम का असर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। लोग वहां भी आस लगाए बैठे हुए है कि वहां सत्ता विरोधी लहर काम आएगी लेकिन अगर काम के आधार पर लोगों ने वोट दिया तो निश्चित रूप से योगी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में लौट सकती है हालांकि यह अभी भविष्य के गर्त में है। यही नहीं 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब बिहार विधान सभा के चुनाव का असर उस पर पड़ेगा फिरहाल तो निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में ममता दीदी को सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव से पहले एक बात लोग और कह रहे थे कि एसआईआर जो हुआ है उसका गलत असर पड़ेगा लेकिन इसका कोई गलत असर नही पड़ा। बल्कि चुनाव में बंपर वोटिंग हुई। इस वोटिंग को देखकर ममता बनर्जी के हाथ पांव फूले हुए है। क्योंकि इस समय वहां पर एसआईआर चल रहा है जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट एसआई आर के मुद्दे पर पहले ही बिहार के कुछ लोगों की याचिका खारिज कर चुकी है तो ममता बनर्जी को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि वहां से उनको राहत नही मिलने वाली है। अब बिहार के बाद बीजेपी का अगला हमला पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है और इसकी कमान गृहमंत्री अमित शाह संभालेंगे । जिस प्रकार बिहार के चुनाव में अमित शाह ने हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनावी रणनीति को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह आगे भी अपना काम दिखाएंगे। इसीलिए तो लोग कहते है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अगर कोई है तो अमित शाह है।

बिहार चुनाव को लेकर के जब भी चर्चा होती थी तो यह बात सामने आई थी कि वहां पर बिना हिंसा या बिना हत्या मर्डर के कोई चुनाव संपन्न नही होता है। लेकिन इस बार बिहार में ना तो कोई हिंसा हुई और ना किसी व्यक्ति की हत्या हुई इसलिए इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष और शांतपूर्ण तरीके से हुआ है। इसके लिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

आमतौर पर देखा गया है कि चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी लहर काम करती है लेकिन बिहार में सत्ता विरोधी लहर ने बिल्कुल काम नहीं किया बल्कि सत्ताधारी पार्टी ने और उनकी सरकार में जो काम किया उसी को आधार मानकर लोगों ने बंपर वोट दिया और यह साबित कर दिया की वह विकास और सुशासन के साथ है उन्हें जंगल राज और झूठे वादे कतई पसंद नहीं हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान महिलाओं ने जमकर वोटिंग की ।

बालश्रम एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या

मो. कामिल खां

भारत में बाल श्रम की स्थिति काफी गंभीर है, जहां लाखों बच्चे विभिन्न उद्योगों में काम करने को मजबूर है बच्चों का एक महत्वपूर्ण यर अनुपात बाल श्रम में लगा हुआ है विशेष कर कृषि, निर्माण एवं घरेलू कार्यों में मजदूरी करते है आंकड़ों की दृष्टि से भारत में 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में लगभग 6 करोड़ बच्चे है भारत में 10 मिलियन से अधिक बच्चे हानिकारक परिस्थितियों में मजदूरी करने को मजबूर है जो कुल बच्चों की कुल आबादी 3.9 फीसदी है ।जो विभिन्न प्रकार के बाल श्रम में लगे है भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चे लगभग 9 मिलियन के आसपास है।

भारत में बच्चों की आबादी में से काफी अधिक संख्या में बच्चे मजबूरी और पेट पालने हेतु काम एवं कच्ची उम्र से ही मजदूरी में लग जाते है एक बार मजदूरी में फंसे बच्चे इसके? बाद बाहर नही निकाल पाते बच्चों के लिए कोई बालश्रम का कार्य की दृष्टि से हानिकारक ही माना जाता है, क्योंकि अपने देश में बालश्रम की स्थिति दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। वास्तव में देश में बढ़ती आबादी,गरीबी, सामाजिक असमानता बाल श्रम के मुख्य कारण है। देश में लगभग दो करोड़ बच्चे बाल श्रम में सक्रियता से लगे है। इनमें 55 फीसदी उत्तर प्रदेश ,बिहार राजस्थान, महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है । हाल के कुछ वर्षों में बालश्रम में कमी आई है ।विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में बाल श्रमिक जहां बढ़े है वही ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या घटी है है । ऐसे में इस महत्वपूर्ण समस्या को निराकरण के लिए प्रयास की जरूरत है।

विडंबना यह है कि विभिन्न प्रयासों से जितने बच्चों को श्रम बाजार से मुक्त कराया जाता है उससे अधिक बच्चे श्रमिक के रूप मे बाजार में पहुंच जाते है जिससे उनकी संख्या में कमी आने के बजाय वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1971 की जनगणना के मुताबिक बाल श्रमिकों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख थे, जो वर्ष 1981 में बढ़कर एक करोड़ 11 लाख हो गई जबकि 1986 में एक करोड़ 73 लाख बताई गई। 1991 मे जनगणना के अनुसार भारत में एक करोड़ 42 लाख 18588 बाल श्रमिक थे 1999 से 2000 में एक करोड चार लाख हो गई 2001 में एक करोड़ 25 लाख बाल श्रमिक लगे थे राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ताजा अनुमानों के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 22 करोड़ के करीब है जो कुल आबादी का 20 फीसदी है। एक स्वयं सेवी संगठन के अनुसार 2.5 करोड़ बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर और दो करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्ण कालिक श्रमिक के रूप में तथा एक करोड़ 50 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्य करते है 2005 में बाल श्रमिकों की संख्या का अनुमान 5 से 6 करोड़ रहा जिसमें वृद्धि हो रही है।

वास्तव में बालश्रम अपने आप में निरीह एवं निरपवाद शब्द है ,किंत जब यह दोनों मिलकर बालश्रम बन जाते है तो एक विकट सामाजिक बुराई का रूप ले लेते है । एक विद्वान के अनुसार, बालश्रम किसी बालक द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिसे सीधे तौर पर स्वयं बालक को या फिर उसके परिवारजनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से किया जाए जिससे उसके स्वयं के शारीरिक ,मानसिक या सामाजिक विकास में बाधा पहुंचे ऐसे बच्चे समाज के लिए देश के लिए चिंताजनक स्थिति है।

बाल श्रमिक मुख्य रूप से दो क्षेत्र में पाए जाते है असंगठित क्षेत्र मे- होटल, ढाबा, फैक्ट्री व दकान आँटो वर्कशॉप अखबार बेचना, कोयला, कचरा चुनना ,खेतीं -बाड़ी ,घर में नौकर का काम करना आदि है । संगठित क्षेत्र मे- कालीन उद्योग ,दियासलाई आतिशबाजी ,हथकरघा चमड़ा ,कांच ,भवन निर्माण पत्थर खदान ,रत्न उद्योग और ताला उद्योग आदि है।

बालश्रम के कारणों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो अत्यधिक निर्धनता, रोजगार के अवसरों कमी कमी अनिश्चित आजीविका और निम्न स्तरीय जीवन- शैली बालश्रम को बड़े पैमाने पर फैलाने मे मुख्य कारण। वैसे शिक्षा का अभाव बाल श्रमिकों के विकास मे काफी सहायक है। पहले खेती के कामों में लगे रहते थे किंतऔद्योगिकरण और शहरीकरण के बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न उद्योंगों एवं व्यवसाय में बाल श्रमिकों को बड़े पैमाने पर नियोजित किया जाने लगा। बाल -बालिका श्रमिक का यौन शोषण मालिकों ठेकेदारों ,एजेंट ,सहकर्मियों, अपराधियो आदि द्वारा किया जाता है ताकि बच्चों में इतना डर पैदा कर दिया जाए कि वह शोषण के विरुद्ध आवाज ना उठा सके ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बाल श्रमिकों कान केवल उनके श्रम का इस्तेमाल होता है बल्कि उनका भरपूर शोषण भी किया जाता है। बाल मजदूरों का शारीरिक शोषण भी इधर बहुत अधिक होने लगा है।सर पर बोझ ढोने ,ज्वलनशील भट्ठियों में काम करने ,कोई चीज खींचने के लिए अंतिम दम तक जोर लगाने, गंदे बदबूदार कार्यों को के कारण उनकी अनुमानित आयु एक तिहाई रह जाती है ।खान एवं खदानों में बच्चों को भेजने की प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि कि उनमें वयस्क नही घुस सकते इसके लिए उनकी मजबूरी होती है कि वह बच्चे सुरंग में जाकर के काम करें । जब वह बड़े होते तो उनकी छटनी कर दी जाती है। शोर करने वाले मशीनो पर प्राय बच्चे बहरे हो जाते है और धूल के कारण उन्हें तरह-तरह की बीमारी हो जाती है।

बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए हमारे देश मे कानूनों की कोई कमी नही है इसमें बाल श्रम की अधिनियम 1986 शामिल है। इसके उपबंधो के अनुसार 13 जोखिम भरी व्यवसायों और 57 जोखिमकारी प्रक्रिया में बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है ।बाल मजदूरों में नियोजकों को संलिप्तता पर उन्हें दंडित किया जाने का प्रावधान भी है। बाल मजदूरी से बच्चों को मुक्त कराने हेतु छापों की पद्धति प्रयोग में लाई जाती है और बच्चों को मुक्त कराया जाता है ,लेकिन जिम्मेदारी की सीमा यही समाप्त नही हो जाती जिससे बच्चों को मुक्त कराया जाय और उसके बाद ही वह समाप्त हो जाती है बल्कि असली जिम्मेदारी की शुरुआत यही से होती है अर्थात मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से समन्वय से विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों का सीधा लाभ बाल मजदूरों को और उनके परिवारो को दिया जाए जिससे उन परिवारों को बाल मजदूरों के जरिए मिलने वाली आय की वैकल्पिक व्यवस्था हो सके और वह इसका लाभ उठा सके इतना ही नही ऐसे गरीब एवं वंचित परिवारों में स्वास्थ्य पोषाहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते खाद्यान्न कपड़े एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिससे उन परिवारों में मृत्यु दर और जन्म दर कम हो तथा उनकी औसत आई बढ़े।

बाल श्रमिकों को मुक्त करने के पश्चात उनके पुनर्वास की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है अन्यथा बाल श्रमिक आजीविका के साधनों से वंचित रह जाए कर और सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख होकर अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते है पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ाना बढ़ावा देने के लिए बैकों द्वारा ऋण की सुविधा दी जाए स्कूली पाठ्यक्रमों में बाल श्रम प्रथा उन्मूलन का अध्याय शामिल किया जाए बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि वह स्कूलों की तरफ जाएं और अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें जिससे बाल मजदूरी पर नियंत्रण किया जा सकता है वैसे यह भी सच है की बाल श्रम उन्मूलन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नही है वास्तव में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए बाल श्रम को एक सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हुए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए इसके लिए जागरूकता की जागरूकता की नितांत आवश्यकता है जिसमें समाज योगदान होना चाहिए । वास्तव में बालश्रम जैसी सामाजिक एवं आर्थिक समस्या के लिए जरूरी है कि बचपन सीखने के लिए है श्रम के लिए नही है ,उनके हाथों में किताबें हों, कारखाने में वह न जाने पाए ऐसी स्थिति में बाल श्रम जैसी देश की प्रमख समस्या पर सरकार के साथ सभी की जिम्मेदारी बनती है ताकि कि इस पर नियंत्रण किया जा सके।

Rashtriya Sahara Page No-6

डिजिटल काबिलियत का लाभ उठाए भारत

अमेरिकी प्लेटफॉर्म उदाहरण के लिए व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक (मेटा) और एक्स का भारत के डिजिटल क्षेत्र में दबदबा है। करोड़ों लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद इनका अधिकांश आर्थिक मूल्य विदेश चला जाता है। अगर प्रति उपयोगकर्ता राजस्व का अनुमान लगाया जाए तो मेटा के 90 करोड़ भारतीय उपभोक्ता ही करीब 45 अरब डॉलर सालाना का आर्थिक मूल्य तैयार करते हैं। गूगल, एमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की डिजिटल मौजूदगी का मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक है जो विदेश जा रहा है।

इसके विपरीत चीन ने शुरुआती दौर में ही विदेशी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और अलीबाबा, टेनसेंट, बायडू, वीबो और बाइटडांस जैसी स्वदेशी कंपनियां विकसित कीं। ऐसा करके उसने 1.4 अरब उपयोगकर्ताओं से जुड़े मूल्य को अपने देश में बनाए रखा। आज बाइटडांस (155 अरब डॉलर) और अलीबाबा (137 अरब डॉलर) जैसी कंपनियां रिलायंस और टाटा जैसे भारत के सबसे बड़े कारोबारी घरानों को टक्कर दे रही हैं। अगर भारत ने शासन और समावेशन के लिए तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसी दिशा में कदम बढ़ाया होता जैसा कुछ अन्य देशों ने किया, तो आज जो राजस्व, नौकरियां और नवाचार विदेश में केंद्रित हैं, वे भारत की अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते थे।

अर्थशास्त्र से इतर उपयोगकर्ताओं के डेटा पर नियंत्रण भी एक बड़ी रणनीतिक ताकत है। आंकड़े उन सामाजिक रुझानों और राजनीतिक मिजाज के बारे में बताते हैं जो बाजार और लोकतंत्र को आकार देते हैं। कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल बताता है कि कैसे फेसबुक के आंकड़े चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं जबकि गूगल और एमेजॉन डेटा का इस्तेमाल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और वाणिज्य पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। यहां तक कि व्हाट्सऐप द्वारा अमेरिकी एजेंसियों को कथित रूप से पिछले दरवाजे से पहुंच मुहैया कराने की खबरें भी भारत की संप्रभुता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती हैं। भारत, जहां लगभग एक अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, उसके लिए अपने डेटा पर संप्रभुता सुनिश्चित करना केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि डिजिटल स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मूल स्तंभ है।

चीन की सरकार नियंत्रित व्यवस्था के उलट भारत में इंटरनेट पूरी तरह खुला और वैश्विक संपर्क वाला है। चीन की राज्य-नियंत्रित फायरवॉल प्रणाली के विपरीत, भारत एक खुला और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ इंटरनेट संचालित करता है। ग्रेट फायरवॉल जैसा मॉडल न तो भारत के लोकतंत्र के अनुकूल है, और न ही उन करोड़ों भारतीयों के लिए जो पहले से वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं।

अजय कुमार

भारत का मार्ग प्रतिस्पर्धा का होना चाहिए, न कि बंदीकरण का। ऐसा मार्ग जिसमें स्थानीय रूप से विकसित प्लेटफॉर्म बनाए जाएं जो उपयोगकर्ताओं को उनकी पसंद से आकर्षित करें, और ऐसा नवाचार, सुरक्षा, और स्थानीय प्रासंगिकता के आधार पर हो।

भारत की सबसे बड़ी चुनौती उन वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्म्स के शक्तिशाली नेटवर्क प्रभावों में निहित है, जहां उपयोगकर्ताओं को उसी प्लेटफॉर्म पर बने रहने से अधिक लाभ मिलता है। यही बात नए प्रतिस्पर्धियों के लिए रास्ता बंद कर देती है। फिर भी, पिछले एक दशक में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया है जब जोमैटो, जोहो, पेटीएम, फोनपे और रेजरपे जैसी भारतीय मूल की डिजिटल कंपनियों ने उभरकर अपनी पहचान बनाई है।इन सफलताओं से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत के डिजिटल उद्यम अब वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था की शीर्ष पंक्ति में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं। आज कई शक्तियां एक साथ मिलकर इस परिवर्तन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम कर रही हैं।

भारत के 90 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के रूप में मौजूद भारी भरकम डिजिटल आधार पर काफी ध्यान केंद्रित है लेकिन वास्तविक कहानी तो इसके आगे है। अगले एक दशक में 50 करोड़ और भारतीय ऑनलाइन होंगे क्योंकि आय, शिक्षा और संपर्क सभी बढ़ रहे हैं। यह अगली लहर भारतीय कंपनियों के लिए एक विशाल और अब तक अप्रयुक्त बाजार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे वे स्थानीयकृत, किफायती और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल समाधान के माध्यम से हासिल कर सकती हैं। जैसे-जैसे स्थानीय प्लेटफॉर्म्स का विस्तार हो रहा है, वे उन उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं जो पहले वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर थे। यह बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, नायिका ने नव-धनाढ्य, नई पीढ़ी के ब्रांड-प्रेमी उपयोगकर्ताओं को वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गजों से अपनी ओर खींचा है। भारत की भाषाई विविधता जो एक समय डिजिटलीकरण को अपनाने में बाधा थी, अब वह एक रणनीतिक बढ़त है। घरेलू प्लेटफॉर्म वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ सकते हैं। स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक सामग्री को लेकर भारतीय स्टार्टअप्स उन बाजारों तक पहुंच सकते हैं जो अब तक अनछुए हैं।

वर्षों से डिजिटल दबदबा नेटवर्क प्रभाव पर निर्भर रहा। ज्यादा उपयोगकर्ताओं का मतलब था बेहतरीन प्लेटफॉर्म। वह तर्क अब खत्म हो रहा है। एआई अब पैमाने पर सीख को तरजीह देता है। जैसा कि अमेरिकी अर्थशास्त्री हाल वैरियन ने 2019 में कहा था, एआई बेहतर आंकड़ों से खुद में सुधार करता है न कि सिर्फ संख्याओं से। बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स बेस्लेन ने दिखाया है कि ओपन-सोर्स एआई ने स्टार्टअप्स के लिए अपनाने की बाधाओं को कम कर दिया है। इस युग में लाभ अब डेटा की गहराई और विविधता तथा एल्गोरिदम की रचनात्मकता से प्राप्त होता है। भारत की विस्तृत, युवा और विविध जनसंख्या के कारण उसके पास सबसे समृद्ध उपयोगकर्ता डेटा सेट्स में से एक है, और वह इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में है। जहां पैमाने से बुद्धिमत्ता की ओर, और नेटवर्क से ज्ञान की ओर बदलाव हो रहा है।

कुछ दशक पहले भारत के डिजिटल स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर हासिल करने के लिए जरूरी निवेशक जुटाने में संघर्ष करते थे। आज देसी कंपनियों ने साबित किया है कि वे नवाचार कर सकती हैं, बड़े पैमाने पर काम कर सकती हैं और एक परिपक्व व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, आधार और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने उद्यमिता के लिए एक मजबूत बुनियाद पैदा की है। यह भारत के लिए उपयुक्त समय है कि वह नए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे। देश की नई पीढ़ी साहसी है, जोखिम लेने वाली है और महत्त्वाकांक्षी भी है। जेनजी का आत्मविश्वास और रचनात्मकता नवाचार को बढ़ावा दे रही है और भारत दुनिया के बेहतरीन डिजिटल उपक्रम तैयार कर रहा है।

ये रुझान भारत से उत्पन्न होने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात को मजबूती देते हैं। सरकार इसे बढ़ावा दे सकती है। दो करोड़ से अधिक कर्मचारियों वाला भारत का सरकारी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े संगठित उपभोक्ता समूहों में से एक है। अगर ये आंशिक तौर पर भी भारतीय प्लेटफॉर्म को अपनाएं तो जबरदस्त प्रभाव पैदा हो सकता है।

भारत अपनी डिजिटल यात्रा के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां वह दुनिया के सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार से आगे बढ़कर डिजिटल शक्ति का प्रमुख उत्पादक बनने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआईसी) द्वारा सभी 'गव डॉट इन' ईमेल और डेटा को जोहो के भारतीय सर्वरों पर होस्ट करने का निर्णय, या अरट्टई को मेसेंजर ऐप के रूप में अपनाना, डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। एक आत्मविश्वासी नई पीढ़ी के नवप्रवर्तकों के साथ, भारत के पास आत्मविश्वास है, जिससे वह अपनी डिजिटल नियति को रचनात्मकता के साथ आकार दे सकता है।

Business Standard Page No-7

वित्त वर्ष 27 का बजट और नई चुनौतियां

उम्मीद है कि बजट विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सुधारों की रफ्तार को तेज करने में मदद करेगा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं एम गोविंद राव

वर्ष 2026-27 की बजट प्रक्रिया अक्टूबर में आरंभ हुई जब इससे संबंधित सर्कुलर जारी हुआ और बजट पूर्व बैठकें आरंभ हुईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा थोपे गए शुल्कों के कारण बढ़ी अनिश्चितता और अस्थिरता तथा इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, साथ ही ट्रंप द्वारा आठ युद्धों को रोकने के दावे के बावजूद अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के जारी रहने के चलते बजट को गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना होगा। उसे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय मजबूती जारी रखनी होगी ताकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और ऋण के अनुपात में कमी लाई जा सके और उसे वर्ष 2031 तक केंद्र सरकार के जीडीपी के 50-52 फीसदी तक लाया जा सके।

इसके अलावा उसे अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 फीसदी के दंडात्मक शुल्क से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को भी राहत दिलानी होगी। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इनमें से कई क्षेत्र श्रम गहन हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद और रसायन। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब तक बजट पेश किया जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो चुका होगा। उस समय व्यापारिक माहौल को लेकर कुछ स्पष्टता आएगी। रूसी तेल आयात को कम करने से कच्चे तेल की आयात लागत बढ़ सकती है और बजट व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है।

अनिश्चित वैश्विक माहौल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहा है और अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 फीसदी की वृद्धि हासिल हुई जो बीती पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। तृतीयक क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन से इस प्रभावशाली वृद्धि को और गति मिली जिसमें 9.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र 7.5 फीसदी की दर से बढ़ा। मांग के क्षेत्र में वृद्धि प्रमुख रूप से पारिवारिक खपत व्यय और केंद्र सरकार के अग्रिम रूप से पूंजीगत व्यय के भरोसे हुई। देश भर में जलाशयों की बेहतरीन हालत के मद्देनजर कृषि उपज अच्छी होने की उम्मीद है। माल एवं सेवा कर में सुधार ने विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई को सितंबर के 57.7 से बढ़ाकर अक्टूबर में 59.2 तक पहुंचा दिया। हालांकि सेवा क्षेत्र के पीएमआई में मामूली कमी आई और यह सितंबर के 60.9 से कम होकर अक्टूबर में 58.9 रह गया। इस आशाजनक प्रदर्शन के चलते रिजर्व बैंक ने वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया है। मुद्रास्फीति की अनुकूल स्थिति को देखते हुए, रिजर्व बैंक संभवतः 3 से 5 दिसंबर की बैठक में नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की और कटौती कर सकता है।

कुल मिलाकर कहें तो, वैश्विक आर्थिक वातावरण के सुस्त और अस्थिर स्वरूप के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में प्रतीत होती है। हालांकि, वृद्धि के परिदृश्य में कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप के शुल्क के प्रभावों का पूरा असर अभी सामने आना बाकी है, और पिछले वित्त वर्ष के आधार प्रभाव के कम होने के साथ वृद्धि की गति भी धीमी पड़ सकती है। हालांकि बड़ी चिंता का मसला निवेश अनुपात है। यह करीब 30 फीसदी के स्तर पर ठहरा हुआ है। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सरकारी निवेश में वृद्धि से ही संभव हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार एवं कम ब्याज दरों के कारण निजी निवेश के आने की उम्मीद कारगर नहीं हुई। वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृद्धि दर को तेज करना आवश्यक है, जिसके लिए निवेश अनुपात में पर्याप्त वृद्धि और वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) में कमी अनिवार्य है। इस मुद्दे को जितना जल्दी संभव हो, उतनी शीघ्रता से संबोधित करना होगा।

वर्ष की पहली छमाही में बजट कार्यान्वयन की प्रगति में कोई विशेष आश्चर्य नहीं देखा गया। महालेखा नियंत्रक द्वारा सितंबर तक के अनुमानित संचयी आंकड़ों के अनुसार, राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 36.5 फीसदी रहा। राजस्व संग्रह बजट अनुमान का 49.5 फीसदी और कुल व्यय 45.5 फीसदी रहा। सरकार ने राजस्व व्यय को नियंत्रित रखा, जो कि अनुमानित राशि का लगभग 43.7 फीसदी है। इसके विपरीत, पूंजीगत व्यय को अग्रिम रूप से खर्च किया गया, जिससे यह बजट अनुमान के 51.8 फीसदी तक पहुंच गया। वर्ष के शेष भाग में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का दबाव हो सकता है, साथ ही अब तक रोक कर रखे गए राजस्व व्यय को जारी करने की आवश्यकता भी हो सकती है इसके अलावा, कॉरपोरेट टैक्स में वृद्धि धीमी रही है, और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी संरचना में बदलाव के प्रभाव सामने आने के साथ-साथ कर राजस्व में कमी देखी जा सकती है। हालांकि यह स्थिति राजकोषीय घाटे को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार अन्य स्रोतों से, विशेष रूप से रिजर्व बैंक के लाभांश से, राजस्व जुटाने में सक्षम हो सकती है।

अगले वर्ष का राजकोषीय गणित चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार ने ऋण-जीडीपी अनुपात को लक्ष्य बनाया है लेकिन संभव है कि वह मुख्यतः राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4 फीसदी तक रखने का लक्ष्य लेकर चले। निजी निवेश में कमी के साथ सरकार को वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए उच्च पूंजीगत व्यय जारी रखना होगा। चुनावी रियायतों के कारण राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में चिंताजनक गिरावट देखी गई है, और राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय पर खुद का धन लगाने का अनुपात भी घटा है, विशेषकर यदि हम केंद्र सरकार द्वारा बिना ब्याज के दिए गए दीर्घकालिक ऋण को घटाकर देखें। संभवतः यह खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने का उपयुक्त समय है। यदि हम यह दावा करते हैं कि गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी आई है, तो 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देना जारी रखने का कोई ठोस कारण नहीं रह जाता। हमारे पास सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए आवश्यक तकनीक और जानकारी उपलब्ध है। हालांकि, राजनीतिक कारणों से ऐसा होना संभव नहीं लगता।

राजस्व के मोर्चे पर वांछित यही है कि सरकार आय कर में अधिक स्पष्टता लाए। दो अलग-अलग आयकर संरचनाओं को जारी रखना तर्कसंगत नहीं है। एक जिसमें उच्च दर पर कर लगाने की प्राथमिकता है और दूसरी जिसमें कम दर पर कर लगाया जाता है। सर्वोत्तम दृष्टिकोण एक ऐसी कर प्रणाली अपनाना है जिसका आधार व्यापक हो और जिसमें कोई कर वरीयता न हो और दरें कम तथा कम भिन्नता वाली हों। इसका उद्देश्य राजस्व जुटाना होना चाहिए, न कि कई लक्ष्यों को एक साथ साधना। ऐसी प्रणाली सरलता सुनिश्चित करती है, संग्रह और अनुपालन की लागत को घटाती है, और अनचाही विकृतियों को जन्म नहीं देती। यह भी उचित होगा कि घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच भिन्न व्यवहार को समाप्त किया जाए। हालांकि सरकार यह दावा करती है कि व्यवसाय चलाना उसका कार्य नहीं है, फिर भी विनिवेश की प्रक्रिया धीमी रही है, और अब समय आ गया है कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए। वास्तव में, सरकार को विनिवेश से भी आगे बढ़कर सभी व्यावसायिक उपक्रमों का निजीकरण करना चाहिए, चाहे वे लाभ में ही क्यों न हों। सरकार का कार्य शासन करना है, व्यवसाय चलाना नहीं। आशा है कि आगामी बजट विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सुधारों की आकांक्षा की लौ को नए सिरे से प्रज्वलित करेगा।

(लेखक कर्नाटक क्षेत्रीय असंतुलन निवारण समिति के अध्यक्ष हैं। वह राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के निदेशक तथा चौदहवें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

Business Standard Page No-7